benefiting only 3.5 percent students of the entire student Community at the cost of primary and vocational educatiin; and

(e) whether Government propose to introduce easy loan based higher education system as existing in several other countries and transfer the resources to primary and vocational education expended today on higher eduction ?

THE MINISTER OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (SHRI ARJUN SINGH) : (a) According to UNESCO Statistical Year Book 1992 India ranks 112th in terms of public expenditure on education as percentage of GNP; however, the Indian expenditure compares very favourable with that in the relevant peer group of other developing countries in Asia.

(b) and (c) The expenditure on Education of the Centre and States was Rs. 17193.66 crores in 1990-91, Rs. 19009.29 crores (RE) in 1991-92 and Rs. 20,750.09 crores (BE) in 1992-93. This expenditure as a percentage of GNP was about 3.6% during the period 1990-91 to 1992-93 as compared to 2.9% in 1965-66 when the Kothari Commission submitted its report. The national resolve has been to achieve the level of 6%. The achievement of this goal is linked with the overall availability of resources and the competing claims of other sectors.

(d) During the year 1992-93 an amount of Rs. 2631.98 crores has been provided for general higher education which forms 12% of the total Education budget of the Central and State Governments. The enrolment in higher education in 1992-93 was 2.6% of the total enrolment.

It is necessary to take a holistic view of the national system. Also, expenditure in one sector of education is not at the cost of other sectors. The Government gives the highest priority to Primary Education but higher education has its own importance as it provides qualified manpower for the national system.

(e) Commercial Banks are already providing educational loans to students pursuing higher education. This facility is expected to increase with time.

जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ का कार्यकरण

*29. श्री ब्रह्मदेव आनन्द पासवान : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कल्याण मंत्रालय के अन्तर्गत जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ (ट्राइफेड) की स्थापना आदिवासियों के कल्याणार्थ की गई है;

(ख) यदि हां, तो जनजातीय सहकारी विपणन संघ की सभी कर्मचारी श्रेणियों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के कार्मिकों की संख्या और उनका प्रतिशत कितना-कितना है;

(ग) बिहार में वित्तीय सहायता के माध्यम से आदिवासियों के उत्थान का कार्य कौन-कौन सी संस्थाएं कर रही हैं और उनसे लाभान्वित आदिवासियों की संख्या कितनी है;

(घ) बिहार में कौन-कौन से जनजातीय अनुसंधान तथा प्रशिक्षण संस्थान कार्यरत हैं;

(ङ) क्या यह भी सच है कि अध्यक्ष का पद रिक्त पड़ा है; और

(च) यदि हां, तो क्या सरकार अध्यक्ष को मनोनीत करने का विचार रखती है और यदि नहीं तो उसके क्या कारण हैं ?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) (क) जी, हां।

(ख) निम्नानुसार :

श्रेणी	संख्या	प्रतिशतता
अनुसूचित जाति	56	19%
अनुसूचित जनजाति	46	15%
सामान्य	196	66%
कुल	298	

(ग) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है। (**नीचे देखिए**)।

(घ) बिहार सरकार द्वारा बिहार आदिवासी कल्याण अनुसंधान संस्थान, रांची की स्थापना की गई है।

(ङ) और (च) जी, नहीं। अध्यक्ष, ट्राइफेड का पद रिक्त है। ट्राइफेड के उप नियम के अनुसार अध्यक्ष का चयन निदेशक मण्डल के निदेशकों में से किया जाएगा। निदेशक मण्डल के 4 आदिवासी प्रतिनिधियों का नामांकन विचाराधीन है। नामांकन होने के बाद निदेशक मण्डल द्वारा निदेशकों में से एक अध्यक्ष का चयन किया जा सकेगा।

विवरण

1992-93 के दौरान बिहार में अनुसूचित जनजाति के लाभ के लिए कार्यरत स्वयंसेवी संगठनों को निर्मुक्त राशियों के ब्यौरे

	संगठन का नाम	राशि (रुपए में)	लाभार्थियों की संख्या
1.	आर० के० मिशन ट्यूबरोक्लोसिस सैनेटोरियम पी० ओ सैनेटोरियम, रांची	10,15,882	92 अंतरंग विस्तर, 10,646 बहिरंग रोगी
2.	आर० के० मिशन विवेकानंद सोसायटी, एल० रोड, बिस्टुपुर, जमशेदपुर	5,11,492	120 अनुसूचित जनजाति छात्र
3.	भारत सेवाश्रम संघ, मुसाबनी बेस्ट, जमशेदपुर	5,38,662	55 अनुसूचित जनजाति छात्र
4.	सोसायटी फॉर रूरल इंडस्ट्रीयलाइजेशन, बरियातु, रांची	2,63,473	225 अनुसूचित जनजाति छात्र

बिहार से बाहर मुख्यालय वाले बिहार में अनुसूचित जनजाति के लाभ के लिए कार्यरत संगठन

1.	अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद, नई दिल्ली	6,62,025	835 छात्र
2.	भारतीय आदिमजाति सेवक संघ, नई दिल्ली	1,39,770	46 छात्र
3.	निखिल भारत वनवासी पंचायत, पश्चिम बंगाल	1,03,108	340 छात्र

Production of Sugar

*30. MISS SAROJ KHAPARDE: Will the Minister of FOOD be pleased to state:

(a) whether Government have taken any steps to boost the production of sugar in the country; and

(b) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF FOOD (SHRI KALP NATH RAI): (a) and (b) Considering the need to boost sugar production during 1993-94 season, Government have initiated the following measures:

(i) A new sugar policy was announced on 16-2-1993. This will help to improve the financial viability of the sugar industry.